भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 902

25 जुलाई, 2023 को उत्तर के लिए नियत

"फेम इंडिया योजना"

902. डॉ.(प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड एण्ड) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया (फेम इंडिया) योजना कार्यान्वित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) फेम के अंतर्गत पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या कितनी है और ईवी अपनाने को बढ़ावा देने में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) सरकार द्वारा देश में ईवी चार्जिंग अवसंरचना विकसित करने और ईवी घटकों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने और उन्हें और अधिक वहनीय बनाने के लिए प्रदान किए गए प्रोत्साहनों और राजसहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ईवी के बारे में जागरूकता फैलाने, कौशल विकास कार्यक्रम चलाने और ईवी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को सहायता प्रदान करने के लिए क्या पहल की गई है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) : जी हां। भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा 01 अप्रैल 2019 से 5 वर्ष की अवधि के लिए कुल 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से फ़ेम इंडिया स्कीम, चरण-II को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस चरण में सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है और मांग प्रोत्सहान के माध्यम से 7090 ई-बसों, 5 लाख ई-तिपहियों, 55000 ई-चौपहिया यात्री कारों और 10 लाख ई-दुपहियों के खरीदारों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है। साथ ही, स्कीम के अंतर्गत चार्जिंग अवसंरचना के सृजन के लिए भी सहायता दी जाती है।

(ख) : फेम इंडिया स्कीम, चरण-II के अंतर्गत बिके इलेक्ट्रिक वाहनों का ब्यौरा 21-07-2023 की स्थिति के अनुसार निम्नानुसार है-

क्र.सं.	वाहन प्रकार	पंजीकृत और पुनः सत्यापित मॉडल	पंजीकृत मूल उपकरण विनिर्माता	फेम-II के अंतर्गत 21.07.2023 की स्थिति के अनुसार बिके वाहनों की कुल संख्या
1	दुपहिया	45	25	7,40,722
2	तिपहिया	96	28	83,420
3	चौपहिया	34	3	8,982
कुल		175	56	8,32,824

[स्रोत: http://fame2.heavyindustries.gov.in/dashboard.aspx]

(ग) : भारी उद्योग मंत्रालय ने फेम इंडिया स्कीम, चरण-I के तहत 520 चार्जिंग स्टेशनों/अवसंरचना को मंजूरी दी थी। साथ ही, इस मंत्रालय ने फेम इंडिया स्कीम, चरण-II के अंतर्गत 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 68 शहरों के लिए 2,877 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों और 9 एक्सप्रेस-मार्गों और 16 राजमार्गों पर 1576 चार्जिंग स्टेशनों को भी संस्वीकृति दी है।

भारी उद्योग मंत्रालय ने 7,432 इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तीन तेल विपणन कंपनियों को पूंजीगत सब्सिडी के रूप में 800 करोड़ रुपये भी संस्वीकृत किए हैं।

(घ) : भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर आर्थिक प्रोत्साहन/सब्सिडी प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

I. **भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया):** सरकार ने शुरूआत में 10,000 करोड़ रुपये की कुल बजटीय सहायता से 1 अप्रैल, 2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए फेम इंडिया स्कीम के दूसरे चरण को अधिसूचित किया। फेम-इंडिया स्कीम चरण-II के तहत, इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद मूल्य में अग्रिम छूट के रूप में प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

II. **ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम**: सरकार ने 15 सितंबर, 2021 को वाहनों के घरेलू विनिर्माण के लिए सहायता प्रदान करने के प्रयोजन से 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम को स्वीकृति दी है। इस पीएलआई स्कीम में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं।

III. **उन्नत रसायन सेल के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम:** सरकार ने 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से देश में उन्नत रसायन सेल के विनिर्माण के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम को 12 मई, 2021 को स्वीकृति दी। इस स्कीम में 50 गीगावाट घंटे के लिए देश में एक प्रतिस्पर्धी उन्नत रसायन सेल बैटरी विनिर्माण व्यवस्था स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। साथ ही, इस स्कीम के अंतर्गत उत्कृष्ट उन्नत रसायन सेल प्रौद्योगिकियों के 5 गीगावॉट घंटे भी शामिल हैं।

IV. इलेक्ट्रिक वाहनों पर वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) 12% से घटाकर 5% और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जर/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दी गई है।

V. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की है कि बैटरी से चलने वाले वाहनों को हरे रंग की लाइसेंस प्लेट दी जाएगी और उन्हें परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

VI. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर पथकर माफ करने की सलाह दी है जिससे इलेक्ट्रिक वाहन की शुरुआती लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

(ड.) : भारत सरकार ने एमिटी विश्वविद्यालय (नोएडा), एनपीटीआई-बदरपुर और एनपीटीआई-फरीदाबाद सहित विभिन्न महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में जागरूकता सृजन करने के लिए विभिन्न पहलें की हैं। साथ ही, भारत के विभिन्न संस्थानों में इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता कार्यक्रम तैयार करने के लिए यह कार्य नैट्रिप के केंद्रों और एआरएआई को भी सौंपा गया है। इंटरनेशनल सेटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईकैट) ने ई-मोबिलिटी पर जागरूकता सृजन के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं-

i. आईकैट में 4 फरवरी, 2023 को "पंचामृत की ओर" विषय पर सम्मेलन और प्रदर्शनी।

ii. 29 मार्च,2023 को "हाउ इज ईवी ड्राइविंग इंडिया ग्रीन मोबिलिटी मिशन" पर इलेक्ट्रिक वाहन संगोष्ठी।

iii. आईकैट में 28 अप्रैल,2023 को "क्या इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र भारत का अगला विकास वाहक बन सकता है" विषय पर संगोष्ठी ।

iv. 11 अगस्त, 2023 को एएटी घटकों और पीएलआई ऑटो स्कीम पर वेबिनार।

v. 22 नवंबर, 2023 को पीएलआई ऑटो सम्मेलन।

vi. 8 दिसंबर, 2023 को विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस सम्मेलन।

vii. 25 जनवरी, 2024 को स्ट्रेंथेनिंग इंडिया ऑटोमोटिव सेक्टर-वे फॉरवर्ड विषय पर सम्मेलन।

***